/font>

Title: Need to accord sanction to the proposal of Government of Rajasthan for inclusion of Mahi Irrigation Project in the Centrally Sponsored Scheme- Laid.

श्री ताराचन्द भगोरा (बांसवाड़ा) : महोदय, राजस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण माही सिचांई परियोजना को केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में सम्मिलित करने हेतु राज्य सरकार ने स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को भेजा हुआ है, परन्तु अभी तक इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हो पायी है। माही सिंचाई परियोजना के अतिरिक्त क्षेत्र 18095 हैक्टर के कुल सिंचित क्षेत्र के प्रस्तावों को राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को 27/6/2001 को प्रेाति किया है। कई बार सम्बद्ध विभाग को स्मरण कराने एवं अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क के बावजूद भी यह योजना स्वीकृत नहीं हुयी है। आयुक्त (सी.ए.डी.) जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार ने सूचित किया है कि इसे दसवीं पंचवर्षीय योजना में विचारार्थ हेतु योजना आयोग को सिफारिश कर दी गयी है। राजस्थान में पिछले चार वर्ो से लगातार अकाल तथा सूखे के कारण इस परियोजना का बहुत ज्यादा महत्व है। मेरी भारत सरकार से मांग है कि माही सिंचाई परियोजना को केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में शीघ्र सम्मिलित करने हेतु अविलम्ब स्वीकृति प्रदान की जाये ताकि अकाल एवं सूखा प्रभावित राज्यों को राहत मिल सके।